बहुजन हिताय! सक्षम भारत बहुजन सुखाय!
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित
www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com
Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI
● वर्ष: 24 ● अंक: 08 ● नई दिल्ली ● सोमवार 13 अक्तूबर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

दिल्ली में कफ सिरप का खौफ, बच्चों की मौत के बाद दवा बाजार में गिरावट, डॉक्टर भी सतर्क

नई दिल्ली । मध्य प्रदेश में कफ सिरप के इस्तेमाल से बच्चों की मौत के बाद राजधानी दिल्ली में भी इसका असर तेजी से देखने को मिल रहा है. दवा कारोबारियों के मुताबिक, सिरप की मांग में 30 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई है. लोग अब सिरप खरीदने से पहले कई बार सोच रहे हैं, वहीं डॉक्टर भी इसे लिखने से परहेज कर रहे हैं. मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के बाद कफ सिरप को लेकर लोगों के मन में गहरा डर बैठ गया है. इसी डर का असर अब राजधानी दिल्ली के दवा बाजार में साफ दिखाई दे रहा है. दवा कारोबारियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में कफ सिरप की बिक्री में 30 प्रतिशत से भी ज्यादा की कमी आई है. पहले जहां लोग बेझिझक बेनाड्रिल जैसे कफ सिरप की मांग करते थे.

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें
E-mail : rmsdp@hotmail.com
अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

अल्पसंख्यकों को खुश करने आप ने पटाखों पर लगवाई थी रोक, बीजेपी का केजरीवाल पर निशाना

नई दिल्ली ।

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप पर आरोप गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि बीते सात-आठ वर्षों में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अल्पसंख्यक समुदाय को खुश करने के लिए ऐसे कदम उठाए, जिनके चलते सर्वोच्च न्यायालय ने दशहरा, दिवाली और दुर्गा पूजा जैसे हिंदू त्योहारों पर पटाखे जलाने पर रोक लगा दी. सचदेवा ने कहा कि,क सरकार ने पर्यावरण के नाम पर न्यायालय में एकतरफा रिपोर्टें पेश कीं, जिससे हिंदू त्योहारों पर पटाखों की अनुमति रोकी जा सके. उनका कहना था कि बीजेपी लगातार कहती रही है कि दिवाली या दशहरे पर कुछ घंटों तक जलने वाले पटाखे दिल्ली के प्रदूषण का मुख्य कारण नहीं है. लेकिन केजरीवाल सरकार ने अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के चलते हिंदू त्योहारों को निशाना बनाया.

खुद ग्रीन पटाखे लाए, फिर खुद ही रोक लगवाई

बीजेपी नेता ने तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार ने पहले ग्रीन पटाखे की पहल की और फिर उन्हीं पर रोक लगाने का माहौल बना दिया. यह दोहरी नीति को दर्शाता है, जिसमें एक तरफ पर्यावरण की चिंता का दिखावा किया गया और दूसरी ओर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई. सचदेवा ने हाल ही में,क नेता सौरभ भारद्वाज के बयान पर भी टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोर्ट अनुमति दे तो दिवाली पर पटाखे जलाए जा सकते हैं. सचदेवा ने कहा कि यह बयान स्पष्ट करता है कि,क आज भी ग्रीन पटाखों की अनुमति के खिलाफ है और प्रदूषण के नाम पर हिंदू त्योहारों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है.

आप नेताओं के ताजा बयानों पर निशाना

बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पिछले सात-आठ वर्षों से पटाखों पर रोक के बावजूद दिल्लीवासी हर साल दिवाली की रात जमकर आतिशबाजी करते रहे, जिससे यह साबित होता है कि जनता इन प्रतिबंधों से सहमत नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों की धार्मिक आस्था की अनदेखी करते हुए कई बार गलत नीतियां लागू कीं.

पटाखे जलाना आस्था का भी है प्रतीक

सचदेवा ने आप से आग्रह किया कि वे नकारात्मक बयानबाजी छोड़ें और ग्रीन पटाखों की अनुमति देने वाले दिल्ली सरकार के प्रस्ताव का समर्थन करें. उन्होंने कहा कि दिवाली पर पटाखे जलाना केवल आनंद का प्रतीक नहीं, बल्कि आस्था का भी प्रतीक है और इस पर रोक लगाने से हिंदू समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचती है.

दिल्ली पुलिस ने चोरी और गुम हुए 101 मोबाइल फोन बरामद, खुशी से खिल उठे लोगों के चेहरे

नई दिल्ली । मोबाइल फोन गुम या चोरी हो जाने पर लोग उसके वापस मिलने की उम्मीद छोड़ देते हैं. महज खानापूर्ति के लिए उसकी गुमशुदगी या फिर चोरी की शिकायत थाने में दर्ज करा कर उसे भूल जाते हैं. लेकिन दिल्ली पुलिस की इस दिशा में किए गए सकारात्मक प्रयास ने अब लोगों के मोबाइल फोन के वापस मिलने की उम्मीद को जगा दी है. दक्षिण-पश्चिम जिले की एंटी-स्नैचिंग सेल ने बेहतरीन काम करते हुए तकनीकी निगरानी और CEIR पोर्टल की मदद से 101 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को वापस सौंपे हैं. अपने मोबाइल वापस पाने के बाद लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं. डीसीपी अमित गोयल के मुताबिक, पिछले दो महीनों में एंटी-स्नैचिंग सेल की टीम ने अथक प्रयासों से इन मोबाइल फोनों को ट्रेस किया. एंटी स्नैचिंग सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर हरि सिंह के नेतृत्व में गठित टीम, जिसमें एसआई कमल कांत, हेड कॉन्स्टेबल शिशराम, मुकेश, नरेंद्र, अनिल और कॉन्स्टेबल सनी शामिल थे, ने तकनीकी डेटा का गहन विश्लेषण किया और IMEI ट्रैकिंग की सहायता से इन मोबाइल फोन का पता लगाने में कामयाबी पाई.

तकनीक और टीमवर्क से मिली कामयाबी

टीम ने CEIR पोर्टल के माध्यम से विभिन्न थानों से समन्वय करते हुए गुमशुदा मोबाइलों को खोज निकाला. इससे पहले, 17 सितंबर को दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा एक सार्वजनिक कार्यक्रम में 34 मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंपे गए थे, जिसमें दिल्ली पुलिस की नागरिक सेवा में उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की गई थी.

नागरिकों ने जताया पुलिस का आभार

इस पहल को आगे बढ़ाते हुए, शेष 67 मोबाइल फोन हाल ही में वसंत विहार स्थित डीसीपी कार्यालय में उनके मालिकों को सौंपे गए. इस मौके पर उपस्थित नागरिकों ने दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस की टीम के समर्पण और मेहनत की सराहना की. उनका कहना था कि ऐसे प्रयास न केवल खोई वस्तुओं को लौटाने में मददगार हैं, बल्कि पुलिस पर जनता के विश्वास को भी और मजबूत बनाते हैं.

ऐसी घटनाओं के लिए दिल्ली पुलिस के प्रयास जारी

जिला पुलिस, नागरिक-केंद्रित पुलिसिंग को और मजबूत करने के लिए ऐसे प्रयास जारी रखेगी. आधुनिक तकनीक और डेटा-आधारित जांच के माध्यम से खोई एवं चोरी हुई संपत्ति की बरामदगी पर फोकस रहेगा. यह अभियान दिल्ली पुलिस के उस मूलमंत्र- With You, For You, Always की सच्ची मिसाल है, जिसका उद्देश्य जनता और पुलिस के बीच विश्वास की डोर को और मजबूत करना है.

दिवाली पर स्वदेशी वस्तुओं की मांग तेज

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी की अपील रंग ला रही है। करवा चौथ, दिवाली और धनतेरस के त्योहारी सीजन में उपभोक्ता दुकानों में भारतीय उत्पादकों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की मांग कर रहे हैं। इसमें विशेष तौर पर खाने-पीने और कपड़ों की मांग प्रमुख है। सजावटी चीजों की खरीद में भी भारतीय वस्तुओं की मांग बनी हुई है। सजावटी वस्तुओं, झालरों, दियों और इलेक्ट्रॉनिक्स की बनी सजावटी चीजों में चीनी माल की खपत कम हुई है, लेकिन इनकी मांग अभी भी बनी हुई है। गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियों के मामलों में भी भारतीय और चीनी उत्पादकों की वस्तुओं में बराबर की खपत बनी हुई है। स्वदेशी वस्तुओं की मांग में तेज बढ़ोतरी से उत्पादकों, व्यापारियों और कामगरों में उत्साह का माहौल है। कपड़ों के मामले में महिलाओं के उत्पाद सेक्टर में सबसे ज्यादा भारतीय उत्पादकों द्वारा बनाए गए कपड़ों की मांग हो रही है। साड़ियां, सलवार सूट और लहंगे जैसी चीजों के मामलों में भारतीय कंपनियों द्वारा बनाए गए उत्पाद महिलाओं को खूब पसंद आ रहे हैं। पुरुषों के कुर्ते-पजामे के मामले में भी भारतीय कंपनियों के उत्पाद खूब डिमांड में हैं। हालांकि, डेनिम और ब्रांडेड कपड़ों के सेक्टर में अभी भी दूसरे देशों में बनी वस्तुएं डिमांड में सबसे ऊपर हैं। दिवाली में केवल एक सप्ताह का समय शेष बचा है। थोक बाजार में सजावटी दीयों, मोमबत्ती, झालरों और सजावटी फूलों की मांग में खूब तेजी देखी जा रही है। सदर बाजार के दुकानदारों के अनुसार, इन वस्तुओं की मांग में स्थानीय उत्पादों का खूब जोर देखा जा रहा है। खुदरा दुकानदारों की ओर से स्थानीय वस्तुओं की मांग की जा रही है। विशेषकर सजावटी मिट्टी के दीयों, झालरों, सजावटी फूलों के मामले में स्थानीय लोगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग हो रही है। इन वस्तुओं को बेहतर कीमत भी मिल रही है। इलेक्ट्रॉनिक दीयों, झालरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के मामलों में भारतीय उत्पादकों की वस्तुएं कम हैं। भारतीय उत्पादक जो वस्तुएं बना रहे हैं, उसमें भी ज्यादातर चीन से मंगाए सामानों की असेंबलिंग ही ज्यादा हो रही है। संभवतः यही कारण है कि इस सेक्टर की चीजों में चीनी वस्तुओं की मांग बनी हुई है। चीन की लंबी झालर सबसे ज्यादा मांग में है। लेकिन ज्यादा समय या लंबे सीजन तक चलने वाली झालरों या लाइटों की मांग में भारतीय उत्पादकों द्वारा बनाई गई झालरों की मांग सबसे ज्यादा है। भगवान गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां बेच रहे मोहम्मद एहसान ने अमर उजाला को बताया कि इस बार कोलकाता की मिट्टी से बनी मूर्तियों की अधिक मांग है।

ओवैसी ने बीजेपी को बताया मजबूत प्रतिद्वंदी, कहा- वे 24 घंटे काम करते हैं; राहुल के अभियान पर भी बोले

नई दिल्ली । एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा को एक मजबूत राजनीतिक प्रतिद्वंदी बताया और कहा कि भाजपा 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी दलों को सतर्क रहना होगा, क्योंकि भाजपा चुनाव में पलभर में बाजी मार सकती है। उन्होंने राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान से खुद को अलग रखते हुए कहा, मैं राहुल गांधी या उनकी पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर भाजपा को हराना है तो जिस तरह वो चुनाव लड़ते हैं, उसी तरह मेहनत करनी होगी। हमें उनके हर कदम पर नजर रखनी होगी। ओवैसी ने एक पुराने अनुभव का जिक्र भी किया, 2009 या 2014 में मेरे संसदीय क्षेत्र में वोटर लिस्ट में डुप्लिकेट नाम थे। हमने जाकर उन्हें चुनौती दी थी। भाजपा एक मजबूत विपक्षी पार्टी है। आप पलक झपकते हैं और वो अपना काम कर लेते हैं। इसलिए सतर्क रहना जरूरी है, वोटर लिस्ट को जांचना जरूरी है। राहुल गांधी अब तक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। 7 अगस्त को दिल्ली में राहुल गांधी ने कर्नाटक की राजधानी बंगलूरू के महादेवपुरा क्षेत्र का हवाला देकर आरोप लगाया था कि वोटर लिस्ट में 1 लाख से ज्यादा गड़बड़ एंट्री हैं, जिनमें डुप्लिकेट वोटर, फर्जी पते और एक ही जगह पर कई वोट शामिल हैं। सितंबर महीने में उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना साधा, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने वालों की जानकारी छुपा रहा है। ओवैसी ने चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में की गई विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह काम जल्दबाजी में किया गया और नागरिकता की जांच गृह मंत्रालय का काम है। ओवैसी के मुताबिक, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 65 लाख नाम हटाए गए और अब आयोग ने और 3.5 लाख नाम भी हटाए हैं। बिहार में बड़ी ग्रामीण आबादी है, और आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया जून में शुरू की थी। बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे, और वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। ओवैसी ने चेतावनी दी- अगर जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं वो जांच नहीं करेंगे, तो मतदान वाले दिन हंगामा होगा। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया है। विशेष गहन पुनरीक्षण वोटर लिस्ट की विशेष समीक्षा होती है। इसमें पुराने, डुप्लिकेट या फर्जी नाम हटाए जाते हैं और नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं। जून 2025 में बिहार में यह प्रक्रिया शुरू हुई थी। जून में मतदाताओं की कुल संख्या 7.89 करोड़ थी। संशोधन के बाद अंतिम सूची में अब 7.42 करोड़ मतदाता बचे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की बात करें तो, बिहार में मतदान 6 और 11 नवंबर को होंगे। मतों की गणना 14 नवंबर को की जाएगी।

अस्थायी जजों की नियुक्ति- सुप्रीम कोर्ट ने दी थी मंजूरी, किसी हाईकोर्ट ने नौ महीने में नहीं की नाम की सिफारिश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में लाखों लंबित आपराधिक मामलों को निपटाने के लिए अस्थायी जजों की नियुक्ति का रास्ता साफ किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने अब तक किसी के नाम की सिफारिश नहीं की है। करीब नौ महीने बीत जाने के बावजूद हाईकोर्ट में इससे जुड़ी कोई पहल नहीं हुई है। शीर्ष कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया से जुड़े लोगों के मुताबिक, 11 अक्तूबर तक देश के 25 में से किसी भी हाईकोर्ट ने अस्थायी जजों की नियुक्ति के लिए किसी नाम की सिफारिश नहीं भेजी है। केंद्रीय कानून मंत्रालय को भी इस संबंध में किसी भी हाईकोर्ट कोलेजियम से कोई सिफारिश नहीं मिली है । सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी को चिंता जताई थी कि देश में 18 लाख से अधिक आपराधिक मामले लंबित हैं। इसको देखते हुए शीर्ष कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को यह अनुमति दी थी कि वे अपने कुल स्वीकृत पदों की 10 फीसदी सीमा तक अस्थायी जज नियुक्त कर सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 224ए के तहत हाईकोर्ट में सेवानिवृत्त जजों को अस्थायी जज के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान है, ताकि मामलों के बोझ को कम किया जा सके। नियम के मुताबिक, संबंधित हाईकोर्ट कोलेजियम अभ्यर्थियों के नाम की सिफारिश कानून मंत्रालय के न्याय विभाग को भेजता है। इसके बाद मंत्रालय उम्मीदवारों की जानकारी जोड़कर फाइल सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को भेजता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम अंतिम फैसला लेकर सरकार से अनुशंसा करता है कि किन व्यक्तियों को जज नियुक्त किया जाए। इसके बाद राष्ट्रपति नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। अस्थायी जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी समान होगी, फर्क केवल इतना होगा कि राष्ट्रपति नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, लेकिन उनकी सहमति आवश्यक होगी। अधिकारियों के मुताबिक, अब तक एक मामले को छोड़कर हाईकोर्ट के अस्थायी जज के रूप में सेवानिवृत्त जज की नियुक्ति का कोई उदाहरण नहीं है।

एंबुलेंस में जीवनरक्षक सुविधाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार से जवाब मांगा

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और अन्य पक्षों से एक याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें एंबुलेंस में हर समय पर्याप्त जीवन रक्षक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।न्यायालय उस याचिका पर भी सुनवाई के लिए सहमत हो गया है जिसमें सड़क एंबुलेंस के संचालन, रखरखाव और नियमन की वर्तमान वास्तविक स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है। प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने 10 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा, नोटिस जारी करें, जिसका चार सप्ताह में जवाब दिया जाए। याचिका में केंद्र, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को पक्षकार बनाया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता पर्सीवल बिलिमोरिया और अधिवक्ता जैस्मीन दामकेवाला याचिकाकर्ताओं सार्थशा पनंगीपल्ली और प्रिया सरकार की ओर से पेश हुए।

पनंगीपल्ली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक रहे प्रख्यात हृदय-वक्ष शल्य चिकित्सक डॉ. पी. वेणुगोपाल की बेटी हैं। प्रिया सरकार वेणुगोपाल की पत्नी हैं। याचिका में कहा गया है, याचिकाकर्ताओं को एंबुलेंस में अपर्याप्त आपातकालीन सुविधाओं का एहसास उस समय हुआ जब डॉ. पी. वेणुगोपाल ने स्वयं अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में जाते समय दम तोड़ दिया, क्योंकि एम्बुलेंस में आपातकालीन जीवन रक्षक सुविधाओं का घोर अभाव था और इसके परिणामस्वरूप उन्हें ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा। याचिकाकर्ताओं ने पाया कि पूरे भारत में एम्बुलेंस में पर्याप्त आपातकालीन संसाधनों की कमी एक बड़ा चिंता का विषय है। याचिका में कहा गया है कि अगर एंबुलेंस में पर्याप्त सुविधाएं होतीं तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। याचिका में कहा गया है कि नीति आयोग की रिपोर्टों के अनुसार भारत में 90 प्रतिशत एंबुलेंस आवश्यक उपकरणों और बुनियादी सुविधाओं जैसे ऑक्सीजन के बिना चल रही है। अपर्याप्त उपकरणों और सुविधाओं के कारण रोगियों की यात्रा के दौरान मौत की संभावना बढ़ जाती है, या गंभीर बीमारी से उबरने की संभावना घट जाती है, जो कि जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। कुछ राज्यों में एंबुलेंस पंजीकरण के लिए शर्तें तय की गई हैं, लेकिन एक बार वाहन पंजीकृत होने के बाद उनकी निगरानी या अनुपालन सुनिश्चित करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

याचिका में यह मांग की गई है

एक प्रभावी कानूनी ढांचा तैयार और लागू किया जाए, जिससे एंबुलेंसों में हर समय पर्याप्त जीवनरक्षक सुविधाएं उपलब्ध रहें। आवश्यक उपकरणों, दवाओं और आपात आपूर्ति की मानक सूची बनाई जाए। एंबुलेंसों में सुविधाओं की कमी, अधिक शुल्क वसूली, लापरवाह ड्राइविंग, देरी या अन्य गड़बड़ियों की शिकायत के लिए हेल्पलाइन स्थापित की जाए।

आखिरकार, हाथ में आया-अवाया शांति का नोबेल

गुरु गुड़ का गुड़ रहा, चेली शक्कर होए! डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ वाकई बुरा हुआ है। बेचारे की वह वाली गत बन रही है, जिसे दुहेली गति कहते हैं। नोबेल कमेटी वालों ने बेचारे की ऐसी गत बनायी है कि बंदे से न हंसते बन रहा है, न रोते। अगला हंसे तो हंसे कैसे? आखिरकार, हाथ में आया-अवाया शांति का नोबेल, आखिरी वक्त में हाथ से निकल गया, जैसे मुट्ठी से रेत फिसल जाए। और यह तब था जबकि नोबेल पुरस्कार अपनी अंटी में करने के लिए, अगले ने इस बार जितनी मेहनत की थी, उतनी मेहनत तो न इससे पहले कभी किसी ने की होगी और न आगे कोई कर पाएगा। पहले लोग समझते थे कि मेहनत तो विज्ञान वगैरह के नोबेल पुरस्कार के लिए करनी पड़ती है। बेशक, थोड़ी-बहुत मेहनत अर्थशास्त्र वगैरह के नोबेल पुरस्कार के लिए भी करनी पड़ती होगी। और हां कुछ न कुछ मेहनत तो साहित्य के नोबल के लिए भी करनी ही पड़ती होगी। लेकिन, शांति का नोबेल, वह तो यूं ही बैठे-बिठाए मिल जाता है। जिसको मिलना होता है, उसकी झोली में खुद ब खुद आ पड़ता है। इसके लिए किसी को कम से ऐसी मेहनत नहीं करनी पड़ती होगी, जो करने वाले के करने से भी ज्यादा, देखने वालों को और यहां तक कि नहीं देखने वालों तक को दिखाई पड़े। पर यह तब की बात है, जब तक व्हाइट हाउस के धराधाम पर ट्रंप का आगमन नहीं हुआ था और आगमन से भी बढ़कर, ट्रंप जी की वापसी नहीं हुई थी। दूसरी पारी में तो ट्रंप जी ने जैसे आते ही एलान कर दिया था, इस बार शांति का नोबेल मेरा। नोबेल के लिए अपुन कुछ भी करेगा। अगले की इच्छा भी गलत नहीं थी। व्हाइट हाउस में वापसी के बाद, क्या था जो अगले के पास नहीं था। सब कुछ तो अगले के पास था। अगले के पास न्यूक्लियर बटन था। अगले के पास दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत थी और आर्थिक ताकत भी। अगले के पास दुनिया में कहीं भी तबाही मचाने की ताकत थी। और तो और, बाद में पता चला कि अगले के पास टैरिफ की तलवार भी थी। मोदी जी की तरह, सारा मीडिया भले ही अगले की गोदी में नहीं था, फिर भी अगले की गोदी में भी काफी मीडिया था। फिर भी ओबामा मिलता था, तो नजरें नीची रखकर निकलना तो दूर रहा, अगला अकड़ के साथ गर्दन तानकर निकलता था। और अकड़ किस बात की? ट्रंप के मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, पावर वगैरह सब है के जवाब में, अगला बस अपने मैडल की ओर इशारा करता था--मेरे पास नोबेल है और वह भी शांति का! पहले नोबेल लेकर आओ, तब करना मुझ से मुकाबला! नोबेल और वह भी शांति का, यही डब्ल्स ट्रबल वाली बात थी। और किसी नोबेल की बात होती, तब तो ट्रंप जी को इतनी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। रसायन या भौतिकी का नोबेल हासिल करना तो ट्रंप जी के लिए बाएं हाथ का खेल था। वैज्ञानिकों को ही तो अपना काम, ट्रंप जी के नाम करने के लिए पटाने की जरूरत होती। कुछ ले-देकर, ट्रंप साहब सौदा पटा ही लेते। बल्कि हमें तो पक्का है कि सौदा भी सस्ते में ही पटा लेते। यूं ही थोड़े ही पूरा जमाना उनकी सौदागरी का कायल है। ट्रंप साहब तो डील की गाजर दिखाकर, बाकायदा युद्ध तक रुकवाने का दावा करते हैं, जैसे भारत-पाकिस्तान का पिछला युद्ध, हालांकि मोदी है कि मानता नहीं है। तब सौदे की गाजर दिखाकर क्या ट्रंप जी किसी वैज्ञानिक का नोबेल लायक काम भी अपने नाम नहीं लिखवा सकते थे? साहित्य को छोड़कर, कोई भी नोबेल ट्रंप जी चुटकियों में अपना बना सकते थे। क्या है कि लेखक-वेखक किसी और ही अकड़ में रहते हैं। रस्सी जली रहती है, पर इनकी अकड़ नहीं जाती। और अर्थशास्त्र के नोबेल पर तो ट्रंप जी कभी भी डायरेक्ट दावा कर सकते थे। अर्थशास्त्र के जानकार नहीं होते, तो क्या धंधे में इतने कामयाब होते। पर शांति का नोबेल? ओबामा ने यहीं फंसा दिया। काश, नोबेल वालों ने युद्ध का नोबेल रख दिया होता। ओटोमैटिकली हर बार अमरीकी राष्ट्रपति को मिल जाता। हर साल नहीं तो भी कम से कम एक कार्यकाल में एक बार तो खुद ब खुद मिल ही जाता। पर नोबेल और वह भी शांति का। वैसे भी नोबेल की कंपनी तो हथियार बनाने की थी, उसे शांति के नोबेल की क्या सूझी? हथियार बनाने वाले भी शांति को प्रमोट करेंगे, तो युद्ध के चाहने वालों की कद्र कौन करेगा? खैर! ट्रंप जी भी दूसरी पारी में पहले दिन से ही भिड़ गए। चेलेंज शांति के नोबेल का था, सो बेचारे को युद्ध रुकवाने के काम में जुटना पड़ा। और अगले ने खोज-खोज कर युद्ध रुकवाए। अफ्रीका तक में छोटे-छोटे युद्ध रुकवाए और बड़ी शान से गिनवाए। बस रूस-यूक्रेन वाला युद्ध ही बार-बार हाथ से फिसलता रहा और रुकते-रुकते, रह गया। इसीलिए तो ट्रंप जी जेलेंस्की और पुतिन, दोनों से बहुत खफा हैं। बस उनसे पक्की वाली कुट्टी नहीं की है, वर्ना बोल-चाल बंद सी ही कर दी है। और गज़ा पर इस्राइल का युद्ध भी। वैसे वह तो शुरू से ट्रंप जी के काबू में था। जिस दिन दिल करता, वार रुकवा देते। बस दो साल दिल ही नहीं किया। सोचा नेतन्याहू को भी अपने मन की कर लेने दें। पर अब और नहीं। दो साल के बाद फिलहाल और नहीं। नोबेल के फैसले के हिसाब से ऐन वक्त पर नेतन्याहू से कह दिया स्टॉप और सारी दुनिया देख रही है कि इस्राइल ने वार रोक दी है। पर क्या फायदा, इतने युद्ध रुकवाने का? दुनिया में इतनी शांति कराने का? नॉर्वे वालों ने नोबेल तो किसी और को दे दिया। कभी-कभी ट्रंप जी को ऐसा लगता है कि अगर फ्रैंड मोदी ने खेल नहीं बिगाड़ा होता, तो शांति का नोबेल उनके ही हाथ होता। पर अगला तो फ्रैंड होकर भी खेल बिगाड़ने पर अड़ गया। जरा सा एक बार युद्ध रुकवाने के लिए थैंक यू कहने में, अगले का क्या जाता था? पर थैंक यू नहीं बोला तो नहीं ही बोला। थैंक यू बोलना छोड़ो, खुद अपने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, पर इशारे से अपने अलग-अलग लेवल के अफसरों को लगा दिया, यह कहने पर कि वॉर रोकी, तो हमने खुद रोकी, उसमें किसी तीसरे का कोई काम नहीं था। यानी ट्रंप की वॉर रुकवाने की कहानी झूठी थी। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ट्रंप की रुकवायी वॉर छह से घटकर पांच रह गयीं। पांच भी क्या छोटी गिनती है? पर माहौल बिगड़ गया। विरोधियों ने कहना शुरू कर दिया कि पांच की गिनती में झोल-झाल लगता है। ठीक से जांच हो। नोबेल कमेटी वाले घोटाले के आरोपों से डर गए। हाय! दुश्मन भी न करे, दोस्त ने वो काम किया है, दोस्ती का नाम बदनाम किया है! पर ट्रंप जी रोयें भी तो रोयें कैसे? शांति का नोबेल मिला तो उनकी चेली, मरिया कोरिना मचाडो को ही है। वेनेजुएला के वामपंथी निजाम का तख्तापलट करने का, उनके उस अमेरिका का ही तो हथियार है मचाडो, जिसे उन्हें अगेन ग्रेट बनाना है। अगेन ग्रेट, माने अगेन दुनिया भर में, जो निजाम पसंद नहीं आए, उनका तख्तापलट! मचाडो की जीत में भी तो, उनकी ही जीत है। उसने भी नोबेल मिलते ही सबसे पहले, ट्रंप का ही थैंक यू किया है। बड़ी चालू रकम है! क्या कीजिए, गुरु गुड़ ही रह जाए और चेला/ चेली शक्कर हो जाए, यह तो हमेशा से होते ही आया है। नोबेल न सही, नोबेल हासिल करने वाली के गुरु का दर्जा सही! दिल को खुश रखने को ट्रंप जी, ये ख्याल अच्छा है!

सम्पादकीय...

सब फेल.....

प्रसिद्ध इतलवी दार्शनिक और राजनीतिज्ञ एंटोनियो ग्राम्शी ने लिखा था, ''पुरानी दुनिया मर रही है और नई दुनिया जन्म लेने के लिए संघर्ष कर रही है। अब राक्षसों का समय है।'' यह बात 2020 के दशक पर भी उतनी ही लागू होती है जितनी 1930 के दशक पर, जब ग्राम्शी ने अपनी मार्क्सवादी विचारधारा को बेनिटो मुसोलिनी की फासीवादी सत्ता के विरुद्ध खड़ा किया था। जिस पुरानी दुनिया को ग्राम्शी ने मरते देखा, वह एडॉल्फ हिटलर और मुसोलिनी जैसे नेताओं और यहां तक कि जोसेफ स्टालिन जो स्वयं एक मार्क्सवादी थे, द्वारा अपनाई गई राक्षसी राजनीति का परिणाम थी। अमरीकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जैसे अन्य लोगों ने अपनी चुप्पी के माध्यम से और ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलेन ने 1938 में हिटलर के तुष्टिकरण के माध्यम से, उस दुनिया के विनाश में तेजी से योगदान दिया। 1930 के दशक की अराजकता के परिणामस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया और एक नई विश्व व्यवस्था का जन्म हुआ। अब, जब लोकतंत्र, वैश्विकता और शांति जैसे स्तंभों पर टिकी वह व्यवस्था चरमरा रही है, विभिन्न देशों में समान चरित्र भारी उथल-पुथल मचा रहे हैं, ग्राम्शी द्वारा ऐसे नेताओं को 'राक्षस' कहना वर्तमान संदर्भ में शायद उचित न हो। फिर भी, आज के युद्धों और अस्थिरता को ग्राम्शी के शब्दों में ही परिभाषित किया जा सकता है। जिस तरह 1930 के दशक में अमरीका द्वारा राष्ट्र संघ में शामिल होने से इंकार करने के कारण उसका पतन हुआ था, उसी तरह नई व्यवस्था की नींव के रूप में स्थापित संयुक्त राष्ट्र, ट्रम्प के शासन में वाशिंगटन से वित्तीय सहायता की कमी के कारण संघर्ष कर रहा है। कई देश इसे एक निरर्थक संगठन मानते हैं जो घटनाओं को प्रभावित करने में असमर्थ है। इस बीच, चीन उस संस्था का उत्साहपूर्वक समर्थन करता दिखाई दे रहा है। वह इस संस्था में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन है। फिर भी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसके सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक आयोजन महासभा, जिसे उन्होंने शायद ही कभी संबोधित किया हो, में बहुत कम रुचि दिखाते हैं। साथ ही, चीन बैल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ग्लोबल डिवेलपमैंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव जैसे ढांचों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक नए संस्थागत ढांचे का सक्रिय रूप से निर्माण कर रहा है। एक नई व्यवस्था के निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करते हुए, शी ने इस वर्ष सितम्बर में ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव के गठन की घोषणा की, जिसका उद्देश्य 'अंतर्राष्ट्रीय शासन प्रणाली में सुधार' करना है। भारत को इन घटनाक्रमों के परिणामों के प्रति सचेत रहना चाहिए। दशकों से बनाए गए रिश्ते अब बिखरते दिख रहे हैं। 'पड़ोसी पहले' नीति के तहत अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, वह एक स्थिर और मैत्रीपूर्ण पड़ोस बनाने में असमर्थ रहा है। उसके कई पड़ोसियों की अस्थिर राजनीति भारत की विदेश नीति की परीक्षा ले रही है। प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल के वादों से बहक कर अमरीका एक बार फिर भारत के कट्टर पश्चिमी प्रतिद्वंद्वी की ओर झुक गया है। यह मान लेना नासमझी होगी कि चीन पाकिस्तान की अमरीका से बढ़ती नजदीकियों से नाखुश था। पिछले कुछ दशकों में, उसने उस देश के राजनीतिक, सैन्य और नागरिक बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया है। पाकिस्तान के प्रस्ताव, चाहे अमरीका के प्रति हों या सऊदी अरब के साथ यह समझौता बीजिंग की जानकारी और सहमति के बिना संभव नहीं होता। 26-27 अक्तूबर को कुआलालम्पुर में होने वाले पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में एक सफलता की उम्मीद है, जहां ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल सकते हैं। हालांकि, दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता शिखर सम्मेलन से पहले समाप्त होने की संभावना नहीं है। टैरिफ पहेली को अंतत हल होने में कुछ और समय लग सकता है।
किसी समझौते के अभाव में, भारतीय पक्ष मोदी-ट्रम्प बैठक को एक निरर्थक कवायद मान सकता है। इसके अलावा, ट्रम्प केवल 26 अक्तूबर का दिन कुआलालम्पुर में बिता रहे हैं और अगले दिन होने वाले शिखर सम्मेलन को छोड़ रहे हैं, जिससे दोनों नेताओं के बीच किसी भी विस्तृत बातचीत की गुंजाइश कम है। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि यह उथल-पुथल एक आदमी की वजह से है। ट्रम्प और 2028 में उनके पद छोड़ने के बाद सामान्य स्थिति फिर से बहाल हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तीन साल का समय बहुत लंबा होता है। ट्रम्प का यह व्यवधान आने वाली नई व्यवस्था के स्वरूप पर अपनी छाप छोड़ेगा। मोदी ने 2 हफ्ते पहले एक महत्वपूर्ण संदेश दिया था जिसमें उन्होंने लोगों से स्वदेशी अपनाने और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने का आह्वान किया था। जबकि वह सराहनीय प्रतिक्रिया है। भारत को तत्काल अपने कूटनीतिक विकल्पों-दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों की व्यापक पुनर्गणना की आवश्यकता है। व्यावहारिकता उसकी रणनीति और कूटनीति की कसौटी होनी चाहिए, रूमानियत नहीं।

उत्सव के ढोल की पोल

अनिल जैन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी सरकार और साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से जीएसटी में कटौती को बचत उत्सव के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इससे देश के लोगों के ढाई लाख करोड़ रुपए बचेंगे। हर चीज के सस्ता होने का ढोल पीटा जा रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक इससे सहमत नहीं है। उसने दो महीने पर होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद बुधवार को जारी रिपोर्ट में कहा कि जीएसटी कटौती का बहुत ज्यादा असर महंगाई पर नहीं पड़ेगा। रिजर्व बैंक की यह सोच उसके फैसले पर भी दिखी। उसने लगातार दूसरी बार ब्याज दर को स्थिर रखा। उसे कम नहीं किया गया, जबकि जीएसटी कटौती से महंगाई कम होने का दावा किया जा रहा था और इस आधार पर माना जा रहा था कि ब्याज दर में कटौती हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपनी रिपोर्ट के एक अलग सेक्शन में आरबीआई की मौद्रिक समिति ने कहा है कि जीएसटी कटौती का महंगाई पर बहुत सामान्य असर होगा। इसका कारण यह है कि महंगाई दर के आकलन में फूड बास्केट का हिस्सा सबसे ज्यादा करीब 60 फीसदी होता है। इसमें दाल, फल, सब्जियों आदि से लेकर मीट, अंडा और दूसरी खाने पीने की चीजें शामिल हैं। इन पर पहले भी शून्य टैक्स था। कुछ खाने-पीने की चीजे पहले से पांच फीसदी के दायरे में थी, जिनमें बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए महंगाई पर इसका ज्यादा असर नहीं होगा।

राज्य सरकारें हो रही हैं कंगाल

एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल (यू) और भाजपा की सरकार ने चुनाव से पहले खजाना खोल दिया और खुले हाथों से हर समूहों के खाते में नकदी डाली है। महिला उद्यमी योजना के नाम पर एक करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाते में 12 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी डाली गई है। इसके अलावा दूसरी कई योजनाओं की घोषणा करके अलग-अलग समूहों के खातों में भी हजारों करोड़ रुपए डाले गए। लेकिन इसके बीच ही महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता और मंत्री छगन भुजबल ने कहा है कि राज्य में लाड़की बहिन योजना के चलते सारी परियोजनाएं ठप्प हो गई हैं। गौरतलब है कि पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लाड़की बहिन योजना शुरू की थी, जिसके तहत महिलाओं के खाते में 1500 रुपए हर महीने डाले जा रहे हैं। इस योजना ने महाराष्ट्र में भाजपा, शिव सेना और एनसीपी गठबंधन की जीत में योगदान दिया लेकिन अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा असर पड़ा है। छगन भुजबल ने कहा है कि सरकार के पास पूंजीगत खर्च के लिए पैसा नहीं है, जिससे विकास परियोजनाएं अटक गई हैं। जो काम हुए हैं, उनके भुगतान के लिए पैसे नहीं हैं। पहले से जारी लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ इस योजना के मिल जाने से सरकार पर बोझ बहुत बढ़ गया है। यही स्थिति झारखंड और मध्य प्रदेश की भी है। अब ऐसा लग रहा है कि इसका चक्र भी पूरा होने वाला है और जल्दी ही पार्टियों को ऐसी योजनाओं से तौबा करना होगा।

कांग्रेस की राजनीति से मायावती चिंतित

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती राहुल गांधी की सामाजिक न्याय की राजनीति को लेकर चिंतित हैं। उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस अगर संगठन के तौर पर मजबूत होती है तो अपना पुराना वोट बैंक वापस हासिल करने के लिए काम करेगी। कांग्रेस असल में यह काम शुरू कर चुकी है। उसने मल्लिकार्जुन खरगे को अध्यक्ष बना कर जो राजनीति शुरू की थी उसे आगे बढ़ा रही है। हर जगह पिछड़ा या दलित चेहरे खोजे जा रहे हैं, संगठन में उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात राहुल गांधी दूसरी पार्टियों के मुकाबले ज्यादा प्रतिबद्धता के साथ कर रहे हैं। उनकी इस राजनीति ने बसपा को चिंता में डाला है। उसका वोट वैसे भी खिसक कर भाजपा की ओर जा रहा है। हालांकि भाजपा नेताओं के बयानों और सोशल मीडिया में उसके समर्थकों द्वारा द्वारा दलित विरोधी अभियान से भाजपा नुकसान में है। उधर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान और आरक्षण को खतरा बता कर पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को एक किया हुआ है। इस सबके बीच मायावती ने करीब नौ साल बाद रैली के जरिये शक्ति प्रदर्शन किया। इस रैली में उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी रही। बसपा की रैली में उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में बिहार से सबसे ज्यादा लोग शामिल हुए। ऐसा लग रहा है कि बिहार में भी राहुल गांधी की दलित राजनीति को पंक्चर करने का प्रयास उत्तर प्रदेश से किया जा रहा है।
बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का विरोध करने वाले संगठनों और बिहार की पार्टियों का कहना है कि उन्होंने सड़कों पर विरोध किया और कानूनी लड़ाई लड़ी इसलिए 69 लाख नाम कटे हैं, अन्यथा डेढ़ करोड़ से ज्यादा नाम काटने की योजना थी। पार्टियों का कहना है कि एसआईआर की घोषणा से पहले चुनाव आयोग से हुई मुलाकात में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि बिहार में 20 फीसदी वोट कटेंगे। 20 फीसदी वोट का मतलब करीब एक करोड़ 60 लाख वोट। उस समय मतदाता सूची में सात करोड़ 90 लाख मतदाता थे। इसी तरह का डर केरल में भाजपा विरोधी पार्टियों को सता रहा है। उनका कहना है कि अगर एसआईआर हुआ तो केरल में एक करोड़ नाम कट सकते हैं।
वहां अभी तीन करोड़ के करीब मतदाता हैं। अगर इनमें से एक करोड़ नाम कटे तो इसका मतलब होगा कि एक तिहाई नाम कट जाएंगे। बिहार में कुल छह फीसदी नाम कटे हैं। केरल में 33 फीसदी नाम काटने की तैयारी है। इस चिंता में केरल विधानसभा में एसआईआर के खिलाफ आम सहमति से प्रस्ताव पास किया गया है। असल में केरल की चिंता उन लोगों की वजह से है, जो खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग खाड़ी देशों में हैं लेकिन उनका नाम केरल की मतदाता सूची में ही है और उनमें से कई लोग चुनाव के समय केरल आते हैं। एसआईआर के दौरान उनमें से कई लोगों के नाम कटने की आशंका है।

कारोबारी की राज्यसभा में जाने की हसरत

पंजाब के सबसे बड़े कारोबारी राजिंदर गुप्ता राज्यसभा में जाने के लिए कोई 20 साल से राजनीतिक हलके में घूम रहे थे। पहले वे कांग्रेस में रहे और फिर आम आदमी पार्टी के साथ हो गए। कांग्रेस से पहले वे अकाली दल और भाजपा के भी करीबी रहे। आखिरकार आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला किया। राज्यसभा से इस्तीफा देकर पंजाब सरकार में मंत्री बने संजीव अरोड़ा की जगह अब राजिंदर गुप्ता को तीन साल के लिए राज्यसभा में भेजा जा रहा है। इस तरह गुप्ता की जो हसरत कांग्रेस ने पूरी नहीं की, वह केजरीवाल ने पूरी कर दी। कांग्रेस के कई नेताओं ने राजिंदर गुप्ता को राज्यसभा भेजने के लिए जोर लगाया था लेकिन पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में राज्यमंत्री का दर्जा दिलाने से ज्यादा वे कुछ नहीं कर पाए। कांग्रेस की सरकार के समय ही 2007 में राजिंदर गुप्ता को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उसके बाद जब प्रदेश में आम आदमी पार्टी का उभार हुआ तो वे उसके साथ चले गए। वहां भी उन्हें आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड का उपाध्यक्ष बना कर राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया। लेकिन गुप्ता का लक्ष्य तो राज्यसभा में पहुंचने का था, सो उन्होंने कोशिशें जारी रखीं। आखिरकार अब केजरीवाल ने उनकी यह इच्छा पूरी कर दी है।
केजरीवाल एक-एक करके पंजाब के उद्योगपतियों और कारोबारियों की राज्यसभा जाने की इच्छा पूरी कर रहे हैं। दिल्ली में भी उन्होंने अपने सजातीय दो ऐसे ही बड़े कारोबारियों को राज्यसभा में भेजा था।

मुत्तकी का भारत दौरा

आजादी के बाद से ही भारत व अफगानिस्तान के सम्बन्ध बहुत मधुर रहे हैं और इस देश के चहुंमुखी विकास में भारत का बहुमूल्य योगदान रहा है। भारत ने इसके आधारभूत विकास में जो योगदान किया वह अभूतपूर्व समझा जाता है क्योंकि 1947 तक यह देश पूरी तरह अविकसित था और कबायली संस्कृति में जी रहा था। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो 1889 तक अफगानिस्तान ब्रिटिश इंडिया साम्राज्य का ही हिस्सा था और इसका शासन कमोबेश तरीके से लन्दन से ही चलता था, हालांकि इसका अमीर या बादशाह भी सत्ता पर काबिज रहता था। मगर 1889 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने इसे स्वतन्त्र देश का दर्जा देने का मन बनाया और 1893 में भारत व अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची जिसे डूरंड लाइन या रेखा कहा जाता है।
अलग देश का दर्जा देने के बावजूद अंग्रेजों ने इसके विदेशी मामलों को अपने नियन्त्रण में ही रखा। अगर इससे भी पिछले इतिहास पर दृष्टि डालें तो 1846 तक यह पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की पंजाब सल्तनत का हिस्सा था जो आगरा से लेकर काबुल तक फैली हुई थी। मगर भारत व अफगानिस्तान का साझा इतिहास यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि प्राचीन काल में सम्राट अशोक के शासन का यह प्रमुख अंग था क्योंकि अशोक महान का साम्राज्य पाटलीपुत्र से लेकर तेहरान (ईरान) तक फैला हुआ था। ईसा पूर्व से लेकर आठवीं सदी तक यह बौद्ध धर्म का गढ़ माना जाता था परन्तु इस सदी में भारत में इस्लाम के आने के बाद यहां इस धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। वर्तमान में अफगानिस्तान एक इस्लामी देश है जहां तालिबान प्रशासन है। अफगानिस्तान से सोवियत संघ की सीमाएं छूती थीं और ईरान से भी इसकी सीमाएं लगती हैं। अतः यह इलाका ब्रिटिश इंडिया के लिए रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा। आजादी मिलने के समय पाकिस्तान बन जाने के बाद यह पाकिस्तान का पड़ोसी देश हो गया परन्तु दोनों ही मुल्कों के इस्लामी देश होने के बावजूद इनके आपस में सम्बन्ध खटास भरे ही रहे और इसकी एक वजह डूरंड लाइन भी रही लेकिन सांस्कृतिक रूप से अफगानिस्तान शुरू से ही भारत के निकट रहा और दोनों देशों के बीच सम्बन्ध भी इसी के अनुरूप रहे। आजकल अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार है जो भारत के साथ अपने सम्बन्ध सुधारना चाहती है। इसी पृष्ठभूमि में तालिबानी सरकार के विदेश मन्त्री श्री अमीर खान मुत्तकी भारत की यात्रा पर आये हुए हैं। उन्होंने विदेश मन्त्री श्री जयशंकर से मुलाकात कर लम्बी बातचीत भी की। इस बातचीत के बाद दोनों देशों की तरफ से एक संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया गया। यह वक्तव्य दोनों देशों के बीच भविष्य में सम्बन्धों की नई नींव डालने वाला माना जा रहा है।
जैसा कि सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजें 2021 तक जमी हुई थीं। इनकी वापसी इसी वर्ष में हुई और तालिबानी शासन काबिज हुआ। सत्ता में आने से पहले तालिबानी संगठन के पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे सम्बन्ध माने जाते थे परन्तु तालिबानी सरकार गठित हो जाने के बाद पाकिस्तान ने अपने रंग दिखाने शुरू किये और यह दोस्ती फीकी पड़ने लगी और दोनों एक-दूसरे के विरोधी जैसे हो गये। पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान उसके पिछलग्गू बनकर रहें जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया और अपनी स्वतन्त्र सोच विकसित की। भारत का अफगानिस्तान में फिलहाल केवल एक तकनीकी विदेश कार्यालय ही है जिसे बहुत जल्दी ही दूतावास में बदला जायेगा। 2021 के बाद वैश्विक परिस्थितियों में भी काफी बदलाव आया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का विरोधी हो चुका है और दूसरा इसका पड़ोसी देश ईरान काफी कमजोर पड़ चुका है। सोवियत संघ के जमाने से ही अफगानिस्तान के सम्बन्ध रूस के साथ काफी प्रगाढ़ रहे हैं मगर फिलहाल रूस-यूक्रेन के साथ अपने ही युद्ध में फंसा हुआ है और जब से डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं तब से अफगानिस्तान के प्रति उनका नजरिया काफी बदला हुआ है। वह लगातार भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान को महत्व दे रहे हैं। तीसरी तरफ चीन का रुख अफगानिस्तान के प्रति बहुत दोस्ताना दिख रहा है। वह तालिबान सरकार के साथ पूर्ण दौत्य सम्बन्ध स्थापित कर चुका है और लगातार इस देश में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। इस सिलसिले में वह राजदूतों की अदला-बदली तक कर रहा है। इस दृष्टि से देखें तो अफगानिस्तान के साथ भारत की दोस्ती होना इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अतः भारत बहुत सोच-समझ कर ही इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और अफगानिस्तान में किये गये अपने भारी निवेश को भी संभाल रहा है। यही वजह है कि संयुक्त वक्तव्य में भारत ने कहा है कि आतंकवाद दोनों देशों के लिए साझा दुश्मन है क्योंकि दोनों को ही सीमा पार आतंकवाद से खतरा है। अतः संयुक्त वक्तव्य में सीमा पार क्षेत्रीय आतंकवाद की पुरजोर मरम्मत की गयी है और कहा गया है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीं और किसी व्यक्ति का इस्तेमाल दूसरे देश में आतंकवाद फैलाने में नहीं करने देगा। साथ ही भारत ने भी कहा है कि वह अफगानिस्तान की अखंडता और संप्रभुता व स्वतन्त्रता के प्रति पूर्णतः समर्पित है। दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग इस दिशा में विकास को बढ़ावा देने वाला होगा। इससे क्षेत्रीय स्तर पर स्थिरता को भी बढ़ावा मिलेगा और भारतीय उपमहाद्वीप में भारत की स्थिति मजबूत होगी जो इस क्षेत्र में शान्ति बनाये रखने में सहायक होगी।

सबको रूला गया, राजवीर जवंदा

कोई आंख नहीं जो रोई न हो, कोई हाथ नहीं जो प्रार्थना और अरदास के लिए जुड़े न हों। लोकप्रिय पंजाबी गायक राजवीर जवंदा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सिर्फ 35 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़ गए। 27 सितंबर को वो गंभीर सड़क हादसे का शिकार हो गए थे, जिसके बाद उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 11 दिनों तक मौत से जंग लड़ने के बाद गुरुवार को सिंगर की मौत हो गई। उनके निधन से पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री, परिवार और प्रशंसकों में शोक व्याप्त है। अब सवाल आता है कि सिंगर का एक्सीडेंट कैसे हुआ था और किन वजहों से उनकी मौत हो गई? दरअसल पूरा मामला शुरू हुआ 27 सितंबर को जब राजवीर अपनी बाइक से शिमला की ओर जा रहे थे। बीच रास्ते में पिंजौर-नालागढ़ रोड पर अचानक उनका सामना दो सांडों से हुआ, जो सड़क पर ही भिड़ गए और उनकी टक्कर के बीच राजवीर की बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और वो खुद को बचाने के चक्कर में एक बोलेरो से टकरा गए। इस भिड़ंत में वो बुरी तरह घायल हो गए और उन्हें आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर की टीम तुरंत ही उनके इलाज में जुट गई लेकिन उन्हें बचाने में असफल साबित हुई। देश अभी एक और गायक जुबीन गर्ग की मौत से उभर भी नहीं पाया था कि एक और गायक हादसे का शिकार हो गया। मैं जवंदा के बारे में इतना कहना चाहती हूं कि 35 साल की उम्र जाने की नहीं होती और दुखदायी पहलू यह है कि उनकी पत्नी बार-बार उन्हें मोटरसाइकिल पर शिमला जाने से रोक रही थी। उन्हें किसी अंदेशे का डर था। सोशल मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उनकी पत्नी ने यह भी कहा कि आज आप बाइक पर मत जाओ लेकिन होनी बहुत प्रबल है। यह हादसा बहुत बड़े सवाल भी छोड़कर चला गया है जो न केवल पंजाब, हरियाणा या हिमाचल की सड़कों पर पशुओं की उपस्थिति से जुड़े हैं। सच बात तो यह है कि राजधानी दिल्ली हो या अन्य शहर, सड़कों पर आवारा पशुओं के जमावड़े हर वक्त दुर्घटना का एक बड़ा कारण बने रहते हैं। इसके लिए क्या व्यवस्था की जानी चाहिए यह काम राज्यों के प्रशासन को करना है लेकिन जाने वाला तो चला गया और हमें अलर्ट करके गया है कि सड़कों पर आवारा पशुओं को आने से रोकने का समय आ गया है। राजवीर ने जाते-जाते दुनिया को यह भी बता दिया है, अगर आप अच्छे इंसान हो, आपके कर्म अच्छे हैं, दुनिया आपको आपके जाने के बाद याद भी करेगी और आपके लिए आंसू भी बहायेगी, प्रार्थना भी करेगी। यह सच है कि जवंदा ने बुलंदी के शिखर पर पहुंचकर भी अपने आपको डाउन टू अर्थ रखा और जिस तरह के गीत गाये वो पंजाब, पंजाबीयत और पंजाबी संस्कृति से जुड़े हैं जिसको बचाए रखने की आज बहुत जरूरत है। मुझे उनकी मां, पत्नी, बच्चों की पीड़ा बहुत ही दुखी कर रही है। सड़कों पर सांड, कुत्ते या गऊ माता खुले घूमते हैं, वे दुर्घटनाओं को खुला आमंत्रण है। सरकारें बहुत कुछ कर रही हैं, ये समस्याएं केवल चंद महानगरों की नहीं पूरे देश के लिए परेशानी का सबब बन चुकी हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पीपलवाला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/570, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादस्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/[illegible])

डॉ. राम मनोहर लोहिया की सामाजिक खिदमात पर डाली रोशनी

सपाईयों ने मनाई डॉ. राममनोहर लोहिया की पुण्यतिथि

मुरादाबाद।

समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर समाजवादी चिंतक डॉ.राममनोहर लोहिया की पुण्यतिथि मनाई। जिसमें सर्वप्रथम पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने लोहिया के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने कहा कि डॉ. लोहिया हमेशा किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों एवं सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलते थे। उन्होंने कभी भी गरीब, किसान, मज़दूर की आवाज़ को दबने नहीं दिया। उनकी लड़ाई हमेश लड़ते रहे। लोहिया जी ने नारा दिया था की जिन्दा कौमें पांच साल इंतजार नहीं करती हैं। हम समाजवादी लोग भी हमेशा लोहिया के आदेशों पर चलकर गरीबों मजदूरों किसानों नौजवानों एवं सभी वर्गों की सेवा कर पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव फ़ुरकान अली ने कहा कि देश की आजादी में उनके द्वारा भारत छोड़ो आदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया तथा देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद आजाद भारत में देश की प्रमुख समस्याओं तथा जनता के हित के लिए समाजवादी विचारधारा के साथ अनेक आंदोलन छेड़ कर जन आंदोलन के नायक कहलाए। श्रद्धांजलि देने वालों मे वेद प्रकाश सैनी,वसीम कुरैशी, संजीव चौधरी, प्रदीप यादव, सुनीता सिंह,गोरव चौहान, सुरेन्द्र शर्मा, योगेन्द्र यादव, बालकिशन शर्मा, तुषार रस्तोगी,आशकर पाशा, वी के सैनी सजीद, कयामुददीन सैफी, राजीव विश्नोई, जिगरी मलिक, पवन कुमार दानिश अली, राजीव यादव, मुकेश यादव, भूरा मलिक,अवनीश यादव,शेखर यादवआदि प्रमुख थे। दूसरी ओर महानगर समाजवादी पार्टी कार्यालय मकबरा पर महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी की अध्यक्षता में स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर उनके विचार उनकी सामाजिक खिदमत उनके इंकलाबी विचारों पर चर्चा की गई और उनके राजनीतिक मार्ग पर चलने की अपील की गई। प्रोग्राम की अध्यक्षता इकबाल हुसैन अंसारी ने की और प्रोग्राम का संचालन डॉक्टर आसिम ने किया। इस कार्यक्रम में सलीम वारसी, लालू परवेज़, फ़हीम मंसूरी, अहमद मुरादाबादी, मोहम्मद नज़ीर अंसारी, मोहम्मद अकरम अंसारी, हाजी राशिद अंसारी, रियासत हुसैन , तरुण गुप्ता ,अमित शर्मा ,सरफराज हुसैन ,मोहम्मद असलम ,मोहम्मद अखलाक, शमशाद अंसारी ,मसरुर हसन, फहीम अंसारी आदि लोग उपस्थित रहे।

औक़ाफ़ की हिफ़ाज़त मुस्लिम समाज की सामूहिक ज़िम्मेदारी है : मौलाना मोहम्मद ताहिर मदनी

*औक़ाफ़ की सुरक्षा और उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के विषय पर कार्यशाला का आयोजन

लखनऊ।

औक़ाफ़ की हिफ़ाज़त और मुतवल्लियों (प्रबंधकों) को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के संबंध में मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से आज जामा मस्जिद, मुंशीपुलिया, इंदिरा नगर में जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द, शहर लखनऊ और मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में मौलाना मोहम्मद ताहिर मदनी, सचिव जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द, पूर्वी उत्तर प्रदेश औक़ाफ़ की शरीअती हैसियत और उसकी अहमियत पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि औक़ाफ़ एक अमानत हैं, जिनकी हिफ़ाज़त पूरी उम्मत की सामूहिक ज़िम्मेदारी है। अगर हमने इसकी सुरक्षा और पंजीकरण में लापरवाही की तो यह सामुदायिक नुकसान का कारण बनेगा। एडवोकेट आफ़ताब अहमद ने वक्फ़ (संशोधन) अधिनियम 2025 के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस क़ानून के लागू होने के बाद अब हर नए वक्फ़ के लिए लिखित वक्फ़-डीड आवश्यक होगी, जिसे वाक़िफ़ (दाता) की ओर से तैयार किया जाएगा। पुराने वक्फ़ जो सर्वे या वक्फ़ बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं, उन्हें तुरंत उम्मीद पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए, और जो संपत्तियाँ अभी तक दर्ज नहीं हैं, उन्हें भी इस पोर्टल के ज़रिए दर्ज किया जा सकता है। इंजीनियर सैयद मोहम्मद शुऐब, पूर्व सीईओ, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 5 दिसंबर 2025 तक सभी मौजूदा वक्फ़ संपत्तियों का पंजीकरण उम्मीद पोर्टल पर अनिवार्य है। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड के एक्ज़िक्यूटिव ऑफिसर एजाज़ अहमद और एस.एम. अफ़ज़ल काशिफ़ ने उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया और मुतवल्लियों को आने वाली तकनीकी परेशानियों के समाधान के लिए मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर वक्फ़ मेल, जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द, पूर्वी यूपी की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर (9569461871) जारी किया गया, ताकि मुतवल्ली रजिस्ट्रेशन से जुड़ी किसी भी तकनीकी दिक़्क़त पर सहायता प्राप्त कर सकें।

विधायक ने किया कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं का सम्मान

मुरादाबाद।

ब्लॉक सभागार कुंदरकी में महिला एवं बाल विभाग विकास द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया ,जिसमें कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह मुख्य अतिथि रहे। कुंदरकी विधायक ने ग्रामीण स्तर पर उत्कृष्ट सेवा दे रही सभी आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया साथ ही उनको मिष्ठान, उपहार और देसी घी देते हुए रोशनी के त्यौहार दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित की। ठाकुर रामवीर सिंह ने बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यकत्रियों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र गाँव के विकास की पहली पाठशाला हैं। एक सशक्त कार्यकत्री ही स्वस्थ, शिक्षित और सक्षम समाज की नींव रखती है। प्रदेश सरकार ब'चों और माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण सुधार के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं का प्रभाव तभी दिखेगा, जब इन्हें गाँव-गाँव तक पहुंचाने का जिम्मा निभाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकत्रियाँ अपने कार्य को इसी तरह पूरी निष्ठा से करती रहेंगी।
विधायक ने विभाग में संचालित अन्य योजनाये जैसे पोषाहार वितरण, हाट कुक मील ,आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले 3-6 वर्ष के ब'चों की शिक्षा पर चर्चा की। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को चुनरी ओढ़ाकर और टीका लगाकर महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी की गई। गर्भवती महिलाओं को उपहार स्वरूप पोषण पोटली भी वितरित की गई। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि गुलाम जिलानी, मेंहदी हसन, मंडल अध्यक्ष संजय कश्यप, बबलू जाटव, आंगनबाड़ी यूनियन उपाध्यक्ष शमीम चौधरी, रविता चौधरी, विनीता गंगवार, निशा चौधरी, अतुल, नूरी मौलाना, इरशाद, अरविंद ठाकुर, पप्पू राजपूत, संजय दिवाकर, नरेश सैनी, मजलूम पाशा सहित सभी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियाँ उपस्थित रहीं।

महानगर में निकली स्वदेशी संकल्प रैली

मुरादाबाद। महानगर में स्वदेशी संकल्प रैली निकली। शहर के प्रमुख बाजारों में निकली इस रैली का मकसद लोगों को स्वदेशी उत्पादों के प्रति जागरूक करना था। ताकि लोग विदेशी उत्पादों का उपयोग करने के बजाए अपने देश में बने स्वदेशी उत्पादों को खरीदें और उनका उपयोग करें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पीएम मोदी लगातार स्वदेशी अपनाने पर जोर दे रहे हैं। मुरादाबाद में इस रैली का आयोजन स्वदेशी जागरण मंच और स्वावलंबी भारत अभियान के तत्वाधान में किया गया। स्वदेशी संकल्प रैली का शुभारंभ शहर विधायक रितेश गुप्ता ने इंपीरियल तिराहे से किया। शहर विधायक ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें स्वदेशी अपनाना होगा। विधायक ने इम्पीरियल से बुध बाजार होते हुए ताड़ीखाना तक इस रैली में हिस्सा लिया। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गौतम बुद्ध पार्क पर समाप्त हुई। बड़ी संख्या में लोग रैली में शामिल रहे।

राय/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा केन्द्रों का एडीएम ने किया निरीक्षण

सुचितापूर्ण ढंग से सकुशल परीक्षा सम्पन्न कराये जाने के दिये गये निर्देश

बहराइच।

उ.प्र. लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा जनपद के 11 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होने वाली सम्मिलित राय/प्रवर अधीनस्थ सेवा तथा सहायक वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रारम्भिक परीक्षा-2025 दो पालियों में सम्पन्न हुई। प्रथम पाली में सम्पन्न होने वाली परीक्षा को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी, सुचितापूर्ण ढंग से सकुशल सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से अपर जिलाधिकारी अमित कुमार ने परीक्षा केन्द्रों महिला पी.जी. कालेज एवं स्वर्गीय ठाकुर हुकुम सिंह किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय तथा पं. वैद्य भगवानदीन मिश्र गांधी इण्टर कालेज का निरीक्षण कर संचालित हो रही परीक्षा का जायज़ा लिया तथा मौके पर मौजूद केन्द्र व्यवस्थापकों तथा स्टैटिक मजिस्ट्रेट को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। एडीएम ने परीक्षा केन्द्रों पर स्थापित कन्ट्रोल का निरीक्षण कर सीसीटीवी कैमरों की क्रियाशीलता का भी जायज़ा लिया। जनपद में परीक्षा के लिए निर्धारित 11 परीक्षा केन्द्रों पर प्रथम पाली में सम्पन्न परीक्षा में परीक्षा केन्द्र राजकीय इण्टर कालेज पर 199, महाराज सिंह इण्टर कालेज पर 201, आज़ाद इण्टर कालेज 199, पं. वैद्य भगवानदीन मिश्र गांधी इण्टर कालेज 198, किसान डिग्री कालेज ब्लाक-ए पर 191, राजकीय बालिका इण्टर कालेज पर 218, राजकीय पॉलीटेक्निक आसाम चैराहा पर 230, किसान डिग्री कालेज ब्लाक-बी पर 191, राजकीय पॉलीटेक्निक, मोहम्मदपुर, नानपारा रोड बहराइच पर 201, महाराजा सुहेल देव स्वाशासी राय चिकित्सा महाविद्यालय बहराइच पर 193 तथा महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय पर 252 परिक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इस प्रकार कुल 4320 परीक्षार्थियों के सापेक्ष कुल 2273 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इसी प्रकार द्वितीय पाली में सम्पन्न परीक्षा में परीक्षा केन्द्र राजकीय इण्टर कालेज पर 199, महाराज सिंह इण्टर कालेज पर 201, आज़ाद इण्टर कालेज 199, पं. वैद्य भगवानदीन मिश्र गांधी इण्टर कालेज 199, किसान डिग्री कालेज ब्लाक-ए पर 192, राजकीय बालिका इण्टर कालेज पर 221, राजकीय पॉलीटेक्निक आसाम चैराहा पर 230, किसान डिग्री कालेज ब्लाक-बी पर 191, राजकीय पॉलीटेक्निक, मोहम्मदपुर, नानपारा रोड बहराइच पर 201, महाराजा सुहेल देव स्वाशासी राय चिकित्सा महाविद्यालय बहराइच पर 194 तथा महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय पर 254 परिक्षार्थी अनुपस्थित रहे।
इस प्रकार कुल 4320 परीक्षार्थियों के सापेक्ष कुल 2281 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे।
उल्लेखनीय है कि महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय हेतु 480 तथा शेष 10 परीक्षा केन्द्रों पर 384-384 परीक्षार्थी आवंटित थे। उल्लेखनीय है कि महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय हेतु 480 तथा शेष 10 परीक्षा केन्द्रों पर 384-384 परीक्षार्थी आवंटित थे।

जमानत लेकर फरार हो गया था एम. फिल. डिग्रीधारी, शातिर तरीके से देता था लूट को अंजाम; पुलिस ने दबोचा

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमएससी और एम.फिल. पास एक लुटेरे को गिरफ्तार किया है। आरोपी डीयू के किरोड़ीमल कॉलेज का छात्र रहा है। उसने कॉलेज से बीएससी ऑनर्स किया हुआ है। आरोपी की पहचान हरिनगर, मोहना गुरुग्राम निवासी दीप शुभम (32 वर्ष) के रूप में हुई है। वर्ष 2017 में आरोपी ने अकेले ही सीतामढ़ी बिहार में बैंक ऑफ इंडिया पर धावा बोलकर वहां से कैश लूट लिया था। लूटपाट के दौरान आरोपी ने रसायन विज्ञान का इस्तेमाल करते हुए पटाखों के साथ कोई केमिकल मिलाकर धुएं वाला बम तैयार किया। उसकी मदद से वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में आरोपी को सजा हो गई थी।

सूचना के आधार पर पुलिस ने दबोचा

आरोपी जमानत लेकर दिल्ली आ गया और कभी कोर्ट का रुख नहीं किया। दिल्ली आने के बाद वर्ष 2021 में आरोपी ने अलग-अलग दो ज्वेलर को निशाना बनाकर लूटपाट की। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाद में वह जमानत पर बाहर आ गया। यहां भी उसने कभी कोर्ट का रुख नहीं किया। अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर रखा था। अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त हर्ष इंदौरा ने बताया कि नौ अक्तूबर को उनकी टीम को सूचना मिली थी कि मॉडल टाउन इलाके में दो ज्वेलर के यहां हुई लूट के मामले में फरार बदमाश हरिनगर, गुरुग्राम आने वाला है। खबर मिलते ही फौरन एक टीम का गठन किया गया। बाद में आरोपी को दबोच लिया गया।

इन मामलों में थी आरोपी की पुलिस को तलाश

छानबीन के दौरान पुलिस 17 सितंबर 2021 को आरोपी ने मॉडल टाउन के गुजरावाला स्थित बी-ब्लॉक में नामी ज्वेलर के यहां लूटपाट की। आरोपी पिस्टल लेकर ज्वेलर के दफ्तर में घुस गया। वहां आरोपी ने उत्तम नगर निवासी महिला कर्मचारी मनमीत गुलेरिया को बंधक बनाकर लूटपाट की।

आरोपी ने वहां से 6.06 लाख रुपये लूट लिए। बाद में जाते समय आरोपी ने मनमीत व सुरक्षा गार्ड को एक जगह बंधक बनाकर उनके मोबाइल फोन भी लूट लिए। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। इसी तरह आरोपी ने 25 अक्तूबर 2021 को गुजरावाला टाउन में ही एक अन्य ज्वेलरी शोरूम से महिला कर्मचारी दर्शिका को बंधक बनाकर 70 हजार रुपये लूट लिए। बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों मामलों में जमानत लेने के बाद आरोपी ने कभी अदालत का रुख नहीं किया और पुलिस से बचने के लिए मोहना, गुरुग्राम में रहने लगा। बिहार बैंक लूट के मामले में आरोपी को सजा हो गई थी। अदालत से मामले में जमानत लेकर आरोपी दिल्ली भाग आया था। बिहार के सीतामढ़ी में पैदा हुआ दीप शुभम परिवार के साथ 1990 के दशक में दिल्ली के बुराड़ी आकर बस गया।

इसके पिता ने दिल्ली आकर अपना कारोबार शुरू कर दिया। भाई भी इंजीनियर बन गया। नानी के यहां रहकर आरोपी ने बिहार के नामी स्कूल से 12वीं कक्षा पास की। बाद में वह दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद उसने नॉर्थ कैंपस के मशहूर कॉलेज किरोड़ीमल में बीएससी ऑनर्स रसायन विज्ञान में 2012 में दाखिला लिया। बाद में आरोपी ने डीयू से ही एमएससी और एम.फिल. रसायन विज्ञान से कर लिया। इसके बाद उसने क्लैट का टेस्ट पास करने के बाद आंध्र प्रदेश के एक कॉलेज में एलएलबी में दाखिला ले लिया।

तालिबान का स्वागत, लेकिन देश के मुसलमानों का क्या...

नई दिल्ली ।

अफगान मंत्री के भारत दौरे को लेकर केंद्र पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर हमला बोला है. महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आप तालिबान का हाथ जोड़कर स्वागत कर रहे हैं, लेकिन पहले आपको यहां के मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, साथ ही उन्होंने केंद्र पर जम्मू-कश्मीर के लोगों की जिंदगी तबाह करने का भी आरोप लगाया. महबूबा मुफ्ती की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत ने अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने का फैसला किया है और वहां के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर हैं.

महबूबा मुफ्ती ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे पर कहा, ‘‘आप तालिबान को आतंकवादी कहते थे और आज उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अपने ही लोगों से ये दुश्मनी क्यों? उनकी लंबी दाढ़ी और पगड़ी है और आप हाथ जोड़कर उनका स्वागत कर रहे हैं, अगर अफगानिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखने से देश को फायदा होता है तो यह ठीक है कि आप तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पहले आपको यहां के मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उनकी मस्जिदों और स्कूलों को तोड़ना बंद करना चाहिए, आपको पहले उनके दिल जीतने चाहिए, जिस जम्मू-कश्मीर ने पाकिस्तान को नकारकर आपसे हाथ मिलाया था, आज आपने उनकी जिंदगी तबाह कर दी है.’’

मुस्लिम आबादी को निशाना बनाने का आरोप

इसके साथ ही उन्होंने एक्स पर अपनी एक पोस्ट में कहा, ‘‘...‘लव जिहाद, ‘जमीन जिहाद, ‘वोट जिहाद और ‘गाय जिहाद के नाम पर भाजपा ने बार-बार अपनी ही मुस्लिम आबादी को निशाना बनाया है और उन्हें बदनाम करने वाले बयान फैलाए हैं. वहीं दूसरी ओर भाजपा के नेतृत्व में लोकतंत्र की जननी भारत ने जिहाद के अग्रदूत तालिबान को अपनाने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए हर तरह की सहायता देने का फैसला किया है, जिसमें अफगान छात्रों को शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करना भी शामिल है.

मुस्लिम आबादी को हाशिये पर डाला जा रहा

पीडीपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया, ‘‘अफगानिस्तान के साथ अच्छे संबंधों को बढ़ावा देना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह एक विरोधाभास को भी जन्म देता है, क्योंकि देश की आजादी, पहचान और प्रगति में योगदान देने वाली भारत की अपनी मुस्लिम आबादी को व्यवस्थित रूप से हाशिये पर डाला जा रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा मुस्लिम छात्रों के लिए छात्रवृत्ति वापस लेना और मदरसे बंद करना ‘‘इस आंतरिक पाखंड की याद दिलाता है. पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाए रखना जरूरी है, लेकिन एक स्थिर और सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र की नींव अपनी सीमाओं के भीतर, खासकर अपने अल्पसंख्यक समुदाय के साथ विश्वास, सम्मान और समानता को बढ़ावा देने में निहित है. उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘उम्मीद है कि बुलडोजर बाबा सुन रहे होंगे.

अफगान विदेशमंत्री की प्रेस-कॉन्फ्रेंस, महिला पत्रकार पहली लाइन में बैठीं

नई दिल्ली । अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने रविवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें महिला पत्रकारों को भी बुलाया गया। प्रेस-कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकार पहली लाइन में बैठीं थीं। इससे पहले शुक्रवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को नहीं बुलाया गया था। इस पर विवाद भी खड़ा हो गया था। मुत्तकी ने पिछली बार महिला पत्रकारों को न बुलाने पर सफाई भी दी। उन्होंने बताया- यह सिर्फ तकनीकी कारणों से हुआ था। पिछली बार पत्रकारों की छोटी लिस्ट तैयार की गई थी, क्योंकि समय कम था। इसके अलावा कोई दूसरा इरादा नहीं था।

मुत्तकी बोले- पिछली बार समय कम था, इसलिए सबको नहीं बुलाया

मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5 अहम बातें...

1. महिलाओं की शिक्षा पर-

मुत्तकी ने कहा कि उनके देश में कुल 1 करोड़ विद्यार्थी स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ रहे हैं, जिनमें 28 लाख महिलाएं और लड़कियां शामिल हैं। धार्मिक मदरसों में भी यह शिक्षा ग्रेजुएशन लेवल तक है। कुछ क्षेत्रों में सीमाएं हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ये शिक्षा के खिलाफ हैं। महिलाओं की शिक्षा को धार्मिक रूप से हराम घोषित नहीं किया गया है, बल्कि इसे अभी दूसरी व्यवस्था तक स्थगित किया गया है।

2. भारतीय दूतावास को फिर से खोलने पर

मुत्तकी ने भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात की और अर्थव्यवस्था, व्यापार और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री ने घोषणा की कि भारत काबुल में अपने मिशन को एम्बेसी में अपग्रेड करेगा और काबुल के डिप्लोमैट्स जल्द ही नई दिल्ली आएंगे।

3. भारत के साथ व्यापार, उड़ान और निवेश पर

बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री ने काबुल और दिल्ली के बीच उड़ानों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की। इसके अलावा दोनों पक्षों ने व्यापार और अर्थव्यवस्था पर समझौता किया। अफगानिस्तान ने भारत को विशेष रूप से खनिज, कृषि और खेल क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया। बैठक में चाबहार बंदरगाह पर भी चर्चा हुई। अफगानिस्तान ने वाघा बॉर्डर को खोलने का अनुरोध किया, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच सबसे तेज और आसान व्यापार रास्ता है।

4. भारतीय पत्रकार की मौत पर दुख जताया

मुत्तकी ने 2021 में अफगानिस्तान में मारे गए भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि पिछले चार साल में अफगानिस्तान में कोई पत्रकार घायल नहीं हुआ। हमें हर मौत का दुख है। उन्होंने कहा कि 40 साल तक सोवियत, अमेरिका और नाटो ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, लेकिन अब देश आजाद है और अपने दम पर खड़ा है। अफगानिस्तान में कोई समस्या नहीं है और वहां सब कुछ ठीक है।

5. पाकिस्तानी लोगों से दिक्कत नहीं, पर कुछ लोग परेशानी पैदा कर रहे

पाकिस्तान के सवालों पर मुत्तकी ने उर्दू में जवाब दिया। उन्होंने कहा- पाकिस्तान की जनता से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन कुछ लोग परेशानी पैदा करते हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की शरारत के जवाब में अफगानिस्तान ने एक ऑपरेशन शुरू किया था, जिसे कतर और सऊदी अरब की मदद से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि हमसे बात करें, हम शांति चाहते हैं, वरना हमारे पास और रास्ते भी हैं। मुत्तकी ने कहा कि पाकिस्तान तालिबान अफगानिस्तान में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को अपने आतंकी ग्रुप्स को रोकना होगा। तालिबान के झंडे की तरफ इशारा करते हुए मुत्तकी ने कहा- यह हमारा झंडा है। इसके लिए हमने जिहाद लड़ा।

दुर्गापुर गैंगरेप केस के तीनों आरोपियों को 10 दिन की पुलिस हिरासत

कोलकाता । पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले को लेकर तीनों आरोपियों को दुर्गापुर कोर्ट में रविवार (12 अक्टूबर, 2025) को पेश किया गया, जहां कोर्ट ने आरोपियों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. दरअसल ओडिशा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष शोभना मोहंती ने राज्य की एक मेडिकल छात्रा के साथ दुर्गापुर में सामूहिक बलात्कार मामले में शामिल सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की रविवार को मांग की थी, जिसे दुर्गापुर कोर्ट से मंजूरी दे दी गई है. ओडिशा के बालासोर जिले की रहने वाली युवती पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी.

शुक्रवार शाम को कुछ लोगों ने कॉलेज परिसर के बाहर उसके साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया. पश्चिम बंगाल पुलिस ने अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मोहंती ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह न केवल ओडिशा के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक दुखद घटना है. उन्होंने

कहा, ‘घटना के प्रकाश में आने के तुरंत बाद, ओडिशा सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया. मुख्यमंत्री ने पीड़िता के परिवार से बात की है.’ मोहंती ने कहा कि वह मामले पर कड़ी नजर रख रही हैं और संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर रही हैं. उन्होंने बताया कि बालासोर जिले से एक टीम पीड़िता को जरूरी मदद पहुंचाने के लिए घटनास्थल पर गई है. OSCW प्रमुख मोहंती ने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए कहा, ‘राज्य (पश्चिम बंगाल) में कानून-व्यवस्था बिगड़ गई है. घटना के 36 घंटे बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दो अन्य अब भी फरार हैं.’ उन्होंने कहा, ‘मैंने सुना है कि आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय से है. मैं बाकी दो आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और इस जघन्य कृत्य में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग करती हूं.’ मोहंती ने कहा कि वह अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर जाकर पीड़िता से मिलने और उसकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी लेने की योजना बना रही हैं.

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया सीएम बनर्जी से अनुरोध

इस बीच, घटना को ‘घृणित और दर्दनाक’ करार देते हुए, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक पोस्ट में कहा, ‘पता चला है कि पीड़िता को चिकित्सा सुविधा मिल रही है. उसके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं. महिलाओं के खिलाफ ऐसी शर्मनाक घटनाओं और अपराधों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है.’ उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से इस जघन्य अपराध के दोषियों की निष्पक्ष जांच, त्वरित कार्रवाई और कड़ी सजा सुनिश्चित करने का आह्वान किया. इसी तरह, ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्तचरण दास ने भी घटना की निंदा की और सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. दास ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘मैं पश्चिम बंगाल में एक उड़िया युवती के साथ सामूहिक बलात्कार की कड़ी निंदा करता हूं. आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. मैंने अपनी महिला शाखा से भी पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है.’

लड़कियों को रात में बाहर नहीं घूमना चाहिए- ममता प्राइवेट कॉलेज छात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लें

कोलकाता । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से गैंगरेप की घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि छात्राओं को रात में बाहर नहीं घूमना चाहिए। खासकर सुनसान इलाकों में सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा- इस घटना की पूरी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की है। निजी कॉलेजों को छात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल, दुर्गापुर रेप केस पर भाजपा और अन्य विरोधी पार्टियां ममता सरकार पर सवाल उठा रही हैं। ओडिशा के सीएम ने भी बंगाल की सीएम से सख्त कार्रवाई करने की मांग की जिसके बाद ममता बनर्जी ने यह बयान दिया है। पश्चिम बंगाल की प्रदेश सचिव और आसनसोल दक्षिण से विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है और बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है।

लालू-राबड़ी के साथ दिल्ली पहुंचे तेजस्वी यादव, राजद सुप्रीमो बोले- सीट बंटवारे पर बातचीत

पटना । बिहार में इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग फंसे पेंच को सुलझाने के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव रविवार को दिल्ली पहुंच गए। उनके साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी दिल्ली पहुंचे हैं। संभावना है कि तेजस्वी यादव आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। संभावना है कि इस बातचीत के दौरान इंडिया गठबंधन में शेयरिंग पर सारी उलझन सुलझ जाए। वहीं लालू और तेजस्वी यादव को कल यानी 13 अक्तूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई लिए उपस्थित भी होना है। दोनों लैंड फॉर जॉब केस में कोर्ट में पेश होंगे। इधर, पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवाल पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कोई भी जवाब नहीं दिया। हालांकि, दिल्ली में जब पत्रकारों ने उनसे सीट बंटवारे को लेकर सवाल पूछा तो कहा कि बातचीत चल रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमलोगों ने कोर्ट ने बुलाया है, इसलिए आए हैं। वहीं सीट बंटवारे के सवाल पर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है। कहीं कोई नाराज नहीं है। जल्द ही सीट बंटवारे की घोषणा कर दी जाएगी। मेरे द्वारा नौकरी देने की घोषणा पर सत्ता पक्ष के लोग परेशान हो रहे हैं। मगर मैंने जो कहा है वह करूंगा। जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी मिलेगी। 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पा लेगी।

वहीं लालू और तेजस्वी यादव को कल यानी 13 अक्तूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई लिए उपस्थित भी होना है। दोनों लैंड फॉर जॉब केस में कोर्ट में पेश होंगे।

राजद ने करीब 80 सीटों पर तय किए अपने उम्मीदवार

वहीं पटना एयरपोर्ट पहुंचने से पहले जब लालू परिवार राबड़ी आवास से निकला तो राजद कार्यकर्ताओं ने राजद सुप्रीमो के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि कुछ सीटों पर वर्तमान विधायकों को टिकट नहीं देने की मांग कर रहे थे। राजद सूत्रों की मानें तो करीब 80 से अधिक सीटें ऐसी हैं, जहां उम्मीदवारों का नाम राजद के शीर्ष नेतृत्व ने कर लिया है। तेजस्वी यादव इस बार खुद ही हर एक सीट पर उतारे गए उम्मीदवार की समीक्षा कर रहे हैं। टिकट उन्हीं को दिया जा रहा है जो मजबूती से राजद का झंडा उस विधानसभा में बुलंद कर हर हाल में जीत दिला सके। वहीं कुछ सीटों पर कांग्रेस अपने खाते में चाह रही है। इसलिए पेंच फंसा हुआ है। जिन विधायकों ने 2020 के विधानसभा चुनाव में काफी अंतर से जीत हासिल की थी, उन्हें हरी झंडी मिल चुकी है। वहीं, कुछ नए चेहरों को भी उनके रिपोर्ट कार्ड देखकर टिकट दिया गया है। इसमें जदयू छोड़कर आए पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, पूर्व विधायक राहुल शर्मा, पूर्व सांसद और बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी समेत कुछ अन्य शामिल हैं।

‘सीएम योगी एक घुसपैठिए....’, अखिलेश यादव ने कर दिया वापस भेजने की मांग

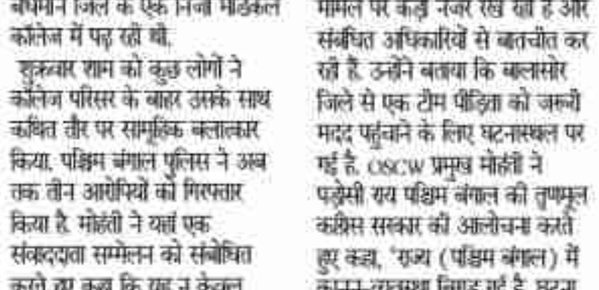

लखनऊ।

अखिलेश यादव ने समाजवाद के प्रणेता राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि के अवसर पर रविवार को लखनऊ के लोहिया पार्क में संवाददाताओं से कहा कि भाजपा के पास झूठे आंकड़े हैं। उन्होंने कहा, अगर उनके आंकड़ों पर भरोसा किया जाए, तो आदमी भटक जाएगा। यादव ने दावा किया, जो लोग पलायन के आंकड़े दे रहे हैं... हमारे उत्तर प्रदेश में भी घुसपैठिए हैं। मुख्यमंत्री उत्तराखंड से हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें उत्तराखंड भेजा जाए। वह अकेले घुसपैठिए नहीं हैं, बल्कि विचारधारा के लिहाज से भी घुसपैठिए हैं। वह (आदित्यनाथ) भाजपा के सदस्य नहीं थे, बल्कि किसी और पार्टी के सदस्य थे। तो, इन घुसपैठियों को कब हटाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में यह दावा किया था कि कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों को वोट बैंक की तरह मानते हैं। उन्होंने सवाल उठाया था कि गुजरात और राजस्थान की सीमाओं पर घुसपैठ क्यों नहीं होती। इस लिहाज से यादव की टिप्पणी महत्वपूर्ण है। शाह ने यह टिप्पणी शुक्रवार को दैनिक जागरण के पूर्व प्रधान संपादक नरेंद्र मोहन की स्मृति में घुसपैठ, जनसांख्यिकीय परिवर्तन और लोकतंत्र विषय पर एक व्याख्यान देते हुए की। इस बीच, अखिलेश यादव की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पीटीआई-भाषा से कहा कि वह जल्द ही इस मुद्दे पर बयान देंगे। राम मनोहर लोहिया को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि राम मनोहर लोहिया जीवन भर अन्याय और गैरजिम्मेदारी के खिलाफ लड़ते रहे। यादव ने कहा, आज हम उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को जनता तक पहुंचाने, उन्हें जागरूक करने और उनके बताए रास्ते पर चलकर सभी के लिए आर्थिक और सामाजिक सम्मान सुनिश्चित करने का संकल्प लेते हैं। जाति एक चिंता का विषय है। डॉ. लोहिया ने भी कहा था कि जाति को तोड़ना चाहिए और जाति को समाप्त करना चाहिए। बाबा साहेब (अंबेडकर) ने जाति के संबंध में कानून भी बनाया, लेकिन आज भी हमें जाति के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

ऑपरेशन ब्लू स्टार पर चिदंबरम की टिप्पणी से सियासी घमासान, बीजेपी बोली- कांग्रेस की गलती उजागर की

नई दिल्ली ।

कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की तरफ से ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर की गई टिप्पणी ने देशभर की सियासत में गर्माहट बढ़ा दिया है। आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति भी अपने चरम पर पहुंच गई है। एक तरह जहां चिदंबरम अपनी टिप्पणी के चलते कांग्रेस नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। वहीं दूसरी ओर अब भाजपा भी इस मुद्दे को आधार बनाकर कांग्रेस पर हमलावर होती दिख रही है।

चिदंबरम कांग्रेस की गलती स्वीकार रहे

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बयान पर भाजपा के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस का घेराव किया। उन्होंने कहा कि चिदंबरम जी कांग्रेस की गलतियां बहुत देर से स्वीकार कर रहे हैं। पहले उन्होंने माना कि अमेरिका के दबाव में 26/11 के बाद कार्रवाई नहीं की जा सकी, अब मान रहे हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार भी एक भूल थी।

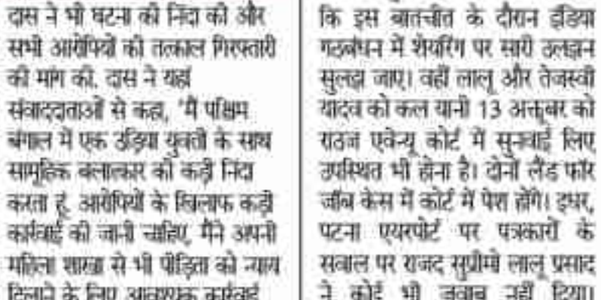

ब्लू स्टार इंदिरा गांधी की राजनीतिक चूक

वहीं भाजपा के प्रवक्ता आरपी सिंह ने मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कोई राष्ट्रीय आवश्यकता नहीं थी, बल्कि इंदिरा गांधी की राजनीतिक चूक थी। उन्होंने 1984 चुनाव से पहले राष्ट्रवाद को भड़काने के लिए सिखों को गलत तरीके से राष्ट्रविरोधी दिखाया। इसका खामियाजा न केवल उन्हें, बल्कि पूरे सिख समुदाय को भुगतना पड़ा। आरपी सिंह ने आरोप लगाया कि दिल्ली और पंजाब में हजारों सिख मारे गए, यह एक सोची-समझी सियासी साजिश थी।

मालवीय बोले- चिदंबरम ने मिथक तोड़ा

इसके साथ ही भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस हमेशा इंदिरा और राजीव गांधी को शहीद बताने का दावा करती रही है, लेकिन अब खुद चिदंबरम ने इस मिथक को तोड़ दिया है। अगर इंदिरा गांधी की हत्या उनकी गलतियों का परिणाम थी, तो क्या कांग्रेस अब चिदंबरम पर कार्रवाई करेगी। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री के इन टिप्पणी से कांग्रेस नेताओं में भी भारी नाराजगी देखी जा रही है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस नेतृत्व चिदंबरम के बयान से बेहद नाराज है और पार्टी को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है।

पार्टी नेतृत्व का मानना है कि वरिष्ठ नेताओं को ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर बयान देने से पहले सतर्क रहना चाहिए।

ऑपरेशन ब्लू स्टार पर क्या बोल गए चिदंबरम

गौरतलब है कि शनिवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम हिमाचल प्रदेश के कसौली में खुशवंत सिंह साहित्य महोत्सव 2025 में पत्रकार हरिंदर बावेजा की पुस्तक दे विल शूट यू, मैडम पर एक चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1984 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत ऑपरेशन ब्लू स्टार की आलोचना की और इसे गलत तरीका बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। पूर्व केंद्रीय गृह और वित्त मंत्री ने कहा कि सिख पूजा स्थल से सेना को बाहर रखकर स्वर्ण मंदिर को पुनः प्राप्त करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर सही तरीका था। उन्होंने कहा कि जून 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार सेना, पुलिस, खुफिया और सिविल सेवाओं का एक संयुक्त निर्णय था। उन्होंने कहा कि यहां किसी भी सैन्य अधिकारी का कोई अनादर नहीं है, लेकिन वह (ब्लू स्टार) स्वर्ण मंदिर को पुनः प्राप्त करने का गलत तरीका था। कुछ साल बाद, हमने सेना को बाहर रखकर स्वर्ण मंदिर को पुनः प्राप्त करने का सही तरीका दिखाया।